जीजेईपीसी भारत-ब्रिटेन सीईटीए लागू होने से पहले उद्योग को कर रही है तैयार

लंदन में क्रेता-विक्रेता सम्मेलन से खुलेंगे व्यापार के नए अवसर

कोलकाता, 9 जुलाई । भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) 15 जुलाई 2026 को लागू हो रहा है, जो भारत के रत्न और आभूषण उद्योग के लिए बड़ा बदलाव और उल्लेखनीय अवसर लेकर आएगा। इससे बाज़ार तक बेहतर पहुंच, अधिक प्रतिस्पर्धात्मकता और प्रमुख निर्यात बाज़ारों में से एक के साथ तेज़ी से द्विपक्षीय व्यापार के रास्ते खुलेंगे। ब्रिटेन को होने वाले लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क मुक्त पहुंच मिलने के मद्देनज़र, इस समझौते से भारतीय विनिर्माताओं, निर्यातकों, एमएसएमई उपक्रमों और कुशल कारीगरों के लिए वृद्धि के बड़े अवसर मिलने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन लंदन में भारतीय उच्चायोग की माननीय मंत्री (आर्थिक) सुश्री निधि मणि त्रिपाठी ने किया। इस मौके पर जीजेईपीसी के चेयरमैन श्री किरीट भंसाली, नेशनल एसोसिएशन ऑफ ज्वेलर्स (एनएजे) के अध्यक्ष श्री मेहदी सादियान, एचएंडटी ग्रुप पीएलसी (ब्रिटेन) की बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग मैनेजर सुश्री केटी कॉथम, और श्री विल इवांस लंदन, निदेशक (एसे मास्टर), एसे ऑफिस, ब्रिटेन के साथ-साथ उद्योग के प्रमुख संबद्ध पक्ष भी मौजूद थे। लंदन में भारतीय उच्चायोग की माननीय मंत्री (आर्थिक), सुश्री निधि मणि त्रिपाठी ने कहा, ''भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारी आर्थिक साझेदारी के लिहाज़ से परिवर्तनकारी कदम है। 15 जुलाई से इस समझौते के लागू होने पर, भारत-ब्रिटेन बायर-सेलर मीट जैसे मंचों की व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देने और नए अवसर पैदा करने में उल्लेखनीय भूमिका होगी। अभी दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग 56 अरब अमेरिकी डॉलर का है, और हम 2030-31 तक इस साझेदारी को 120 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं।'' जीजेईपीसी के अध्यक्ष, श्री किरीट भंसाली ने रत्न और आभूषण क्षेत्र से जुड़े अवसरों के बारे में कहा, ''भारत-ब्रिटेन सीईटीए के लागू होने से भारत का रत्न और आभूषण उद्योग प्रतिस्पर्धा के लिहाज़ से लाभप्रद स्थिति में होगा। 15 जुलाई से ब्रिटेन के बाज़ार में बिना किसी शुल्क (ड्यूटी-फ्री) के पहुंच मिलने से भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ेगी और प्रमुख उत्पाद श्रेणियों में नए अवसर पैदा होंगे। हमें भरोसा है कि अगले कुछ वर्षों में ब्रिटेन को भारत का रत्न और आभूषण निर्यात मौजूदा 754 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर लगभग 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर हो जाएगा, साथ ही इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग 7 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा।'' जीजेईपीसी में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों के संयोजक, श्री विजय मंगुकिया ने कहा, ''भारत-ब्रिटेन बायर-सेलर मीट, भारत-ब्रिटेन सीईटीए के लागू होने से पहले दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मज़बूत करने की जीजेईपीसी की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। जीजेईपीसी इस मंच के ज़रिये प्रत्यक्ष व्यापारिक संवाद को आसान बनाने के अलावा, इस साल सितंबर में 'ज्वेलरी शो लंदन' में 'इंडिया पवेलियन' के ज़रिए ब्रिटेन के बाज़ार में भारत की मौजूदगी बढ़ाएगी। हम ब्रिटेन के भागीदारों के साथ मिलकर खरीदारों के प्रतिनिधिमंडलों को आईआईजेएस भारत प्रीमियर और जयपुर में होने वाले 'इंटरनेशनल जेम एंड ज्वैलरी शो' (आईजीजेएस) में लाने का भी प्रयास कर रहे हैं, ताकि दोनों बाज़ारों में व्यापार, सोर्सिंग और दीर्घकालिक साझेदारी के लिए लगातार अवसर पैदा किए जा सकें।'' दो दिन की इस बायर-सेलर मीट में भारत के 20 प्रमुख विनिर्माता भाग ले रहे हैं, जो विभिन्न किस्म के हीरे जड़े आभूषण, रंगीन रत्नों वाले आभूषण, चांदी के आभूषण और प्रयोगशाला में बने हीरे वाले आभूषण प्रदर्शित कर रहे हैं। वे ब्रिटेन के 50 से अधिक बड़े खरीदारों (जिनमें खुदरा श्रृंखला, थोक विक्रेता और स्वतंत्र खुदरा वक्रता रिटेलर शामिल हैं) के साथ जुड़ेंगे। इससे एफटीए से तैयार अवसरों को लंबे समय की वाणिज्यिक भागीदारी में तब्दील करने का मंच मिल रहा है।

नालको और एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने अनुगुळ में 1,080 मेगावाट का कैप्टिव पावर प्लांट स्थापित करने के लिए संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए

नई दिल्ली, 9 जुलाई । नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) और एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) ने आज ओडिशा के अनुगुळ में 4ह्न270 मेगावाट (1,080 मेगावाट) थर्मल कैप्टिव पावर प्लांट (सीपीपी) विकसित करने के लिए 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी (संयुक्त उद्यम कंपनी) के गठन के लिए संयुक्त उद्यम-सह-शेयरधारक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता नई दिल्ली में कोयला और खान मंत्री के श्री जी. किशन रेड्डी, माननीय कोयला और खान मंत्री की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में हस्ताक्षरित हुआ। इस अवसर पर श्री सनोज कुमार झा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, अपर सचिव, कोयला मंत्रालय एवं अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक एनएलसीआईएल-- अतिरिक्त प्रभार, श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, नालको, श्री विवेक कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय भारत सरकार, श्री जगदीश अरोड़ा, निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी), नालको, श्री अभय कुमार बेहुरिया, निदेशक (वित्त), नालको, डॉ. प्रसन्न कुमार अचार्या, निदेशक (वित्त), एनएलसीआईएल के साथ कोयला और खान मंत्रालय, नालको तथा एनएलसीआईएल के के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। संयुक्त उद्यम कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत शामिल किया जाएगा, जिसका पंजीकृत कार्यालय चेन्नई और कॉर्पोरेट कार्यालय भुवनेश्वर में होगा। नालको और एनएलसीआईएल प्रत्येक के पास 50% इक्विटी होगी। संयुक्त उद्यम कंपनी, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के तहत 100% विद्युत की खरीद के लिए नालको के साथ 25 साल की विद्युत खरीद समझौता तथा कोल इंडिया द्वारा अधिसूचित कीमतों पर कोयले के लिए एनएलसीआईएल के साथ दीर्घकालिक ईंधन आपूर्ति समझौता करेगा। यह समझौता भारत सरकार के खान और कोयला मंत्रालय के तहत दो नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के बीच रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उल्लेखनीय है कि यह विकास 14 फरवरी 2026 को चेन्नई में नालको और एनएलसीआईएल के बीच हस्ताक्षरित गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन (एमओयू) के बाद हुआ है, जिसने थर्मल और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना विकास और दीर्घकालिक कोयला आपूर्ति व्यवस्था में सहयोग के लिए व्यापक रूपरेखा स्थापित की है। उल्लेखनीय है कि देश में एल्यूमिना और एल्यूमिनियम के एक प्रमुख निर्माता के रूप में नालको ओडिशा के अनुगुळ में 0.5 एमटीपीए एल्यूमिनियम प्रद्रावक विस्तार का कार्य कर रहा है, जिसकी शुरुआत 2030-31 में होने की आशा है, जिसके लिए 800 मेगावाट अतिरिक्त कैप्टिव विद्युत की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी चरणबद्ध तरीके से एनएएलसीओ के मौजूदा सीपीपी परिसर में अनुगुळ में 4ह्न270 मेगावाट ब्राउनफील्ड थर्मल क्षमता वृद्धि विकसित करेगा। कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा खपत दायित्व (आरसीओ) मानदंडों के अनुरूप 200-250 मेगावाट की फर्म नवीकरणीय ऊर्जा (आरई-आरटीसी) का भी अनुसरण करेगी, जिसमें एनएलसीआईएल अपने नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो से दीर्घकालिक विद्युत क्रय समझौतों (पीपीए) या समूह कैप्टिव व्यवस्था के माध्यम से समर्थन का विस्तार करेगा। कोयला मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न लोक उद्यम एनएलसीआईएल, जिसके पास लिग्नाइट और कोयला खनन और थर्मल/नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में छह दशकों से अधिक का अनुभव है, परियोजना निष्पादन क्षमता और सुनिश्चित दीर्घकालिक कोयला आपूर्ति से समृद्ध है, जिसमें ओडिशा में अनुगुळ स्थल के निकट स्थित इसकी माचाकाटा कोयला खान भी शामिल है।

चॉइस इंटरनेशनल ने एनएच इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की

कोलकाता, 9 जुलाई । भारत के प्रमुख डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज़ ग्रुप में से एक, चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड (''चॉइस'') ने आज एनएच इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज कंपनी लिमिटेड (एनएचआईएस) के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की।एनएचआईएस दक्षिण कोरिया का एक प्रमुख फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और एनएच फाइनेंसियल ग्रुप की सब्सिडियरी है।यह पार्टनरशिप चॉइस की ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट शाखा, चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड में 9000 मिलियन के निवेश के ज़रिए की गई है। यह स्ट्रैटेजिक निवेश चॉइस की ग्रोथ यात्रा में एक अहम पड़ाव है और यह दक्षिणकोरिया के प्रमुख फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनएच इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीजका चॉइस के उस विज़न में भरोसा दिखाता है, जिसके तहत भारत में अगली पीढ़ी का फाइनेंशियल सर्विसेज़ प्लेटफ़ॉर्म बनाया जा रहा है।इस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के सहारे, चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड का लक्ष्य अगले तीन सालों में अपने ब्रोकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बिज़नेस में 5 गुना ग्रोथ हासिल करना है, साथ ही अपनी डिजिटल क्षमताओं, इंस्टीट्यूशनल फ्रैंचाइज़ और कस्टमर प्रपोज़िशन को मज़बूत करना है। इस डेवलपमेंट पर बात करते हुए, चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड के सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, श्री अरुण पोद्दार ने कहा, ''यह इन्वेस्टमेंट हमारी ग्रोथ की यात्रा में एक अहम पड़ाव है और यह हमारे विज़न, बिज़नेस मॉडल और लंबे समय की क्षमता पर एक प्रमुख ग्लोबल फाइनेंशियल संस्थान के भरोसे को दिखाता है।

कोलकाता की आवासीय मांग H1 2026 में स्थिर बनी रही : नाइट फ्रैंक इंडिया

कोलकाता, 9 जुलाई । नाइट फ्रैंक इंडिया ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट इंडिया रियल एस्टेट: रेजिडेंशियल एंड ऑफिस (जनवरीह्नजून 2026) का 2026 में कहा कि नई परियोजनाओं की सीमित रफ्तार के बावजूद 2026 की पहली छमाही में कोलकाता का आवासीय बाजार स्थिर बना रहा। आवासीय बिक्री 3% वार्षिक आधार पर बढ़कर 8,368 यूनिट रही, जबकि आवासीय लॉन्च 5% वार्षिक आधार पर घटकर 7,316 यूनिट रह गए, क्योंकि डेवलपर्स ने नई आपूर्ति को लेकर अनुशासित रुख अपनाया। लॉन्च में आई इस नरमी की एक वजह राज्य में चुनाव की अवधि के दौरान परियोजना घोषणाओं में आई अस्थायी सुस्ती भी रही। कोलकाता के अपेक्षाकृत किफायती आवासीय बाजार, बेहतर होती कनेक्टिविटी और विस्तारित होते इन्फ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क के चलते मांग को समर्थन मिलता रहा। आवासीय कीमतों में 5% वार्षिक आधार पर बढ़कर 5,942 प्रति वर्ग फुट हो गईं, जबकि अविक्रित इन्वेंटरी 9% वार्षिक आधार पर घटकर अब तक के सबसे निचले दर्ज स्तर 18,578 यूनिट। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2025 में एक दशक के सबसे मजबूत वार्षिक प्रदर्शन के बाद, कोलकाता के कार्यालय बाजार में लीजिंग गतिविधि में नरमी देखी गई। H1 2026 में कार्यालय लेनदेन 0.8 मिलियन वर्ग फुट रहे, जो वार्षिक आधार पर 26% की गिरावट दर्शाते हैं, जिसकी वजह पिछले वर्ष जैसे बड़े लेनदेन का अभाव और विस्तार को लेकर ऑक्युपायर्स का सतर्क रुख है। कम लीजिंग वॉल्यूम के बावजूद, प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में मांग स्वस्थ बनी रही, रिक्तता (वेकेंसी) घटकर 27.5% के अपने सबसे निचले दर्ज स्तर पर आ गई, जबकि औसत कार्यालय किराए में 15% वार्षिक आधार पर वृद्धि हुई, जिसकी वजह ग्रेड ए कार्यालय स्थानों की निरंतर मांग और प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में सीमित उपलब्धता है। जॉयदीप पॉल, सीनियर डायरेक्टर- ऑक्युपायर स्ट्रैटेजी एंड सॉल्यूशंस, नाइट फ्रैंक इंडिया ने कहा, ''2025 में असाधारण लीजिंग गतिविधि के बाद, 2026 की पहली छमाही के दौरान कोलकाता का कार्यालय बाजार सुदृढ़ीकरण के एक स्वस्थ दौर से गुजरा। बड़े आकार के सौदों की अनुपस्थिति के कारण कुल लेनदेन मात्रा में नरमी आई, लेकिन शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में ऑक्युपायर मांग स्थिर बनी रही। ग्रेड ए कार्यालय संपत्तियों के प्रति निरंतर वरीयता, घटते वेकेंसी स्तर और साल्ट लेक सिटी तथा राजारहाट न्यू टाउन में मजबूत किराया वृद्धि, कोलकाता के वाणिज्यिक रियल एस्टेट बाजार की बेहतर होती बुनियादी स्थितियों को दर्शाते हैं। आगे चलकर, टली हुई ऑक्युपायर आवश्यकताओं के साथ गुणवत्तापूर्ण कार्यालय स्टॉक की सीमित उपलब्धता से आने वाली तिमाहियों में लीजिंग की गति को समर्थन मिलने की उम्मीद है।

कैच ने लॉन्च किया नया कैंपेन; इंडस्ट्री में पहली बार पेश की 'फ्लिप टॉप' पैकेजिंग

कोलकाता, 9 जुलाई । धरमपाल सत्यपाल ग्रुप (डीएस ग्रुप) के पॉपुलर ब्रांड 'कैच साल्ट एंड स्पाइसेज' ने अपने मटर पनीर ब्लेंडेड मसाला के लिए उद्योग में पहली बार फ्लिप-टॉप बाहरी पैकेजिंग और प्रेस लॉक सुविधा पेश की है। कंपनी ने इस नई पैकेजिंग को एक नए टेलीविजन विज्ञापन (टीवीसी) के जरिए लॉन्च किया है। उपभोक्ताओं की बदलती जरूरतों, सुविधा और फ्रेशनेस को ध्यान में रखते हुए इस पैकेजिंग को डिजाइन किया गया है, ताकि मसालों की खुशबू बरकरार रहे, उन्हें आसानी से निकाला जा सके, पैक को वापस सुरक्षित तरीके से बंद किया जा सके और स्टोर करने में भी कोई दिक्कत न हो। खाने के दौरान, एक महिला खाने के बेहतरीन स्वाद और खुशबू से इम्प्रेस होकर मजाक में कहती है, क्या खुशबू क्या स्वाद, जी करता है खाना बनाने वाले के हाथ चूम लूं! उसे लगता है कि खाना अक्षय कुमार ने बनाया है। तभी अक्षय, राजपाल यादव की तरफ इशारा करते हैं, जो बड़े गर्व से क्रेडिट लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा देते हैं। यह देखकर वह महिला थोड़ी असहज हो जाती है। इसके बाद अक्षय कुमार मजाकिया अंदाज में बीच-बचाव करते हुए बताते हैं कि असली क्रेडिट कैच मटर पनीर मसाला को जाता है। इस पर वह महिला शर्माते हुए कहती है कि उसे तो पहले से ही पता था कि इस लाजवाब स्वाद के पीछे कैच मटर पनीर मसाला ही है, जिसके बाद सब हंसने लगते हैं। इस कमर्शियल में नए फ्लिप टॉप + प्रेस लॉक पैकेजिंग को बहुत ही सहज तरीके से दिखाया गया है, जिसमें यह भी बताया गया है कि पैकेट खुलने के बाद भी यह पैकेजिंग मसालों की फ्रेशनेस, खुशबू और टेस्ट को लंबे समय तक बनाए रखती है। डीएस ग्रुप के कैच साल्ट एंड स्पाइसेज, सीनियर जनरल मैनेजर (मार्केटिंग) अर्नब घटक चौधरी ने कहा, डीएस ग्रुप में हमारा फोकस हमेशा से ही कंज्यूमर की सुविधा और इनोवेशन पर रहा है। हम जानते हैं कि लोग ऐसी स्पाइस पैकेजिंग चाहते हैं जो यूज करने, रीसील करने और स्टोर करने में आसान हो। यह अनोखी पैकेजिंग हमारे इसी कमिटमेंट का नतीजा है। यह कैंपेन रोजमर्रा के कुकिंग एक्सपीरियंस को और आसान, स्मार्ट और मजेदार बनाने की हमारी कोशिश को दिखाता है क्योंकि खाना सिर्फ खाना नहीं होता। डेंट्सु क्रिएटिव वेबचटनी के सीईओ और चीफ क्रिएटिव ऑफिसर, सुरजो दत्त ने कहा, क्रिएटिव नजरिए से हमारा मकसद कैच के इस नए प्रोडक्ट इनोवेशन को एक बेहद सिंपल, यादगार और एंटरटेनिंग तरीके से पेश करना था। नया फ्लिप टॉप पैक और प्रेस लॉक पाउच मसालों को फ्रेश रखने के लिए ही बनाया गया है, और हम इस बात को एक मजेदार कहानी के जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। अक्षय कुमार और राजपाल यादव की एवरग्रीन केमिस्ट्री ने इस एड में एक अलग ही जान, ह्यूमर और अपनापन डाल दिया है, जो लोगों को काफी पसंद आएगा।

कोलकाता और मऊ के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन जारी रहेगा

कोलकाता, 9 जुलाई । यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए, रेलवे ने मऊ-कोलकाता-मऊ स्पेशल ट्रेन की सेवा को मौजूदा रूट और स्टॉपेज के साथ जारी रखने का फैसला किया है। 05096 मऊ-कोलकाता स्पेशल ट्रेन 22.07.2026 से 23.09.2026 के बीच हर बुधवार को (10 फेरे) मऊ से 13:20 बजे रवाना होगी और अगले दिन 08:50 बजे कोलकाता पहुंचेगी। वहीं, 05095 कोलकाता-मऊ स्पेशल ट्रेन 23.07.2026 से 24.09.2026 के बीच हर गुरुवार को (10 फेरे) कोलकाता से 13:20 बजे रवाना होगी और अगले दिन 08:40 बजे मऊ पहुंचेगी। यह ट्रेन रास्ते में ईस्टर्न रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आने वाले नैहाटी, बांडेल, बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर और जसीडीह स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रुकेगी।

आईआईटी मंडी ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र के लिए परिचालनात्मक भूस्खलन पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित की

मंडी, 9 जुलाई । जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में भूस्खलन की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। भारतीय हिमालयी क्षेत्र (Indian Himalayan Region - IHR) विशेष रूप से इस आपदा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, जहां हर वर्ष अनेक ढलानों के ध्वस्त होने से जन-धन की भारी हानि होती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मंडी के वैज्ञानिकों ने एक पूर्णतः परिचालनात्मक लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम (LEWS) विकसित किया है। इस शोध का नेतृत्व आईआईटी मंडी के स्कूल ऑफ सिविल एंड एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग के प्रो. डेरिक्स प्रेज़ शुक्ला ने किया। इस शोध में उनके शोधार्थी अंकित सिंह और नितेश धीमान भी शामिल रहे। लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम (LEWS) एक ऐसी पूर्व चेतावनी प्रणाली है जो स्थलाकृति की संवेदनशीलता और वास्तविक समय (रियल-टाइम) वर्षा संबंधी आंकड़ों के आधार पर भूस्खलन की संभावना का पूर्वानुमान लगाती है। यह प्रणाली संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए समय रहते चेतावनी जारी करती है, जिससे प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियां आवश्यक एहतियाती कदम उठा सकें। इस प्रणाली के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रो. डेरिक्स प्रेज़ शुक्ला ने कहा, ''मानसून की शुरुआत के साथ ही हमारा लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम (LEWS) वेब-आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से प्रतिदिन भूस्खलन का पूर्वानुमान उपलब्ध कराता है। यह प्रणाली उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहले से पहचान करने में मदद करती है, जिससे प्रशासन और स्थानीय समुदाय समय पर निकासी एवं आपदा तैयारी जैसे आवश्यक कदम उठा सकें।'' उन्होंने आगे कहा कि उपग्रह आधारित पूर्व चेतावनी प्रणालियां आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सबसे प्रभावी निवेशों में से एक हैं, क्योंकि ये वैज्ञानिक आंकड़ों को समय पर उपयोगी निर्णयों में बदलने में सक्षम बनाती हैं। इस प्रकार का क्षेत्रीय स्तर का भूस्खलन पूर्वानुमान मंच विशेष रूप से मानसून के दौरान, जब भूस्खलन का खतरा सबसे अधिक होता है, आपदा प्रबंधन एजेंसियों की तैयारी, त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वय को उल्लेखनीय रूप से मजबूत कर सकता है। भारत में उपलब्ध अन्य भूस्खलन पूर्व चेतावनी प्रणालियों की तुलना में आईआईटी मंडी का डएथड पूरे भारतीय हिमालयी क्षेत्र को कवर करता है, जिससे यह देश की सबसे व्यापक प्रणालियों में से एक बन गया है। इस प्रणाली को शोधकर्ताओं ने बहु-स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किया। सबसे पहले भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के डेटाबेस से लगभग 26,000 भूस्खलन घटनाओं का विश्लेषण कर भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्र तैयार किया गया। इसके लिए विभिन्न भूस्खलन कारकों को एन्सेम्बल मशीन लर्निंग मॉडल की सहायता से एकीकृत किया गया। इसके बाद P-RIL (Probability of Rainfall-Induced Landslides) मॉडल विकसित किया गया, जिसमें NASA Global Landslide Catalogue और IMERG उपग्रह वर्षा डेटा से प्राप्त सात वर्षा मानकों का उपयोग किया गया। चूंकि वर्षा की स्थिति लगातार बदलती रहती है, इसलिए यह मॉडल पिछले 15 दिनों के वर्षा आंकड़ों के आधार पर गतिशील पूर्वानुमान प्रदान करता है। अंतिम दैनिक भूस्खलन पूर्वानुमान स्थिर संवेदनशीलता मानचित्र और गतिशील P-RIL मॉडल को संभाव्यता विश्लेषण के माध्यम से एकीकृत कर तैयार किया जाता है। उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए पूर्वानुमानों को विभिन्न जोखिम श्रेणियों (Risk Categories) के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हितधारकों तक जानकारी आसानी से पहुंचाने के लिए आईआईटी मंडी की टीम ने Google Earth Engine (GEE) आधारित वेब पोर्टल विकसित किया है। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता वर्तमान दिन के साथ-साथ पिछले तीन दिनों के भूस्खलन पूर्वानुमान देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे झ्रक्ष बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं तथा चयनित स्थानों के लिए व्हाट्सएप अलर्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार, यह लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम समय पर और स्थान-विशिष्ट चेतावनियां जारी कर भारतीय हिमालयी क्षेत्र में आपदा तैयारी और जोखिम न्यूनीकरण को मजबूत करेगा तथा आर्थिक नुकसान को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

महाआचार्य सौरभ जे. सरकार भारतीय कृषक समाज के राज्य अध्यक्ष - पश्चिम बंगाल नियुक्त

कोलकाता, 9 जुलाई । भारतीय कृषक समाज ने महाआचार्य सौरभ जे. सरकार को अपना राज्य अध्यक्ष - पश्चिम बंगाल नियुक्त किया है। नियुक्ति पत्र इसी सप्ताह के आरंभ में नई दिल्ली में श्री कृष्ण बीर चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय कृषक समाज (बीकेएस) द्वारा, अन्य राज्यों के बीकेएस प्रतिनिधियों की उपस्थिति में औपचारिक रूप से सौंपा गया। यह नियुक्ति पश्चिम बंगाल में संगठन के कार्य के एक नए चरण का प्रतीक है, जिसका केंद्र किसानों की आय में वृद्धि, प्राकृतिक कृषि, प्रौद्योगिकी सशक्तिकरण, बेहतर बाज़ार संपर्क, बीज संप्रभुता, किसान गरिमा और मज़बूत ग्रामीण संस्थाएँ हैं। बीकेएस प्रतिनिधियों ने महाआचार्य जी को बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल इकाई राज्य भर के कृषकों, बटाईदारों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण उद्यमियों की सेवा में और अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनेगी। बीकेएस की पश्चिम बंगाल शाखा को एक किसान केंद्रित मंच के रूप में आकार दिया जा रहा है, जो किसानों की आवाज़ सुनता है, धैर्यपूर्वक संगठन करता है, और कृषकों को सुदृढ़, लाभकारी एवं पारिस्थितिक रूप से संतुलित कृषि की ओर बढ़ने में सहयोग देता है। इसकी प्राथमिकताओं में प्रशिक्षण एवं क्षेत्रीय संगोष्ठियाँ, प्राकृतिक एवं रसायन सचेत खेती, जैविक एवं देशज आदान, मूल्य संवर्धन, किसान उद्यमिता, नीति प्रतिक्रिया, तथा कृषि में युवाओं और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी शामिल महाआचार्य जी के अनुसार, अपने अगले संगठनात्मक कदमों के अंतर्गत बीकेएस पश्चिम बंगाल कोलकाता में एक औपचारिक कार्यक्रम आयोजित करने, राज्य, मंडल एवं ज़िला स्तर की इकाइयाँ स्थापित करने, तथा श्री कृष्ण बीर चौधरी के मार्गदर्शन में अन्य राज्यों के नेताओं के साथ-साथ पश्चिम बंगाल के माननीय मंत्रियों एवं वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को आमंत्रित करने की योजना बना रहा है। राज्य इकाई किसानों के लिए एक व्यावहारिक सहायता उपकरण के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को लागू करने की भी तैयारी कर रही है, जिसमें स्थानीय भाषा परामर्श, बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण, बाज़ार आसूचना और संरचित किसान प्रतिक्रिया प्रणालियाँ शामिल हैं। संगठन ने कहा, ''भारतीय कृषक समाज भारतीय किसान के गरिमा, न्यायसंगत नीति, आत्मनिर्भरता और उस व्यावहारिक ज्ञान के अधिकार के लिए खड़ा है, जो मिट्टी, बीज या सामुदायिक जीवन को कमज़ोर किए बिना आय बढ़ाता है।

टीआरएआई के ड्राइव टेस्ट से गैंगटोक, पाक्योंग और एनएच-310 कॉरिडोर में मोबाइल नेटवर्क प्रदर्शन का हुआ खुलासा

गैंगटोक, 9 जुलाई । भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी टीआरएआई ने मोबाइल नेटवर्क सेवाओं की वास्तविक समय की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए गैंगटोक और पाकयोंग जिलों के साथ-साथ सिक्किम में एनएच-310 पर देओराली बाजार से नाथू ला दर्रा तक के हिस्से में किए गए एक इंडिपेंडेंट ड्राइव टेस्ट के निष्कर्ष जारी किए हैं। टीआरएआई के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय की देखरेख में 8 और 9 मई को किए गए इन परीक्षणों के तहत 102.8 किलोमीटर शहरी मार्गों, 66.5 किलोमीटर राजमार्गों और पांच हॉटस्पॉट स्थानों को कवर किया गया। इस मूल्यांकन में 2जी, 3जी, 4जी और 5जी नेटवर्क पर लाइव वॉयस और डेटा सत्रों का उपयोग करके कवरेज, कॉल ड्रॉप दर, कॉल सेटअप सफलता दर, आवाज की गुणवत्ता, डाउनलोड व अपलोड गति, लेटेंसी और पैकेट लॉस सहित प्रमुख गुणवत्ता मापदंडों का विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट में विभिन्न ऑपरेटरों के नेटवर्क प्रदर्शन में अंतर देखा गया। रिलायंस जियो ने शहरी क्षेत्रों में 63.89 एमबीपीएस और राजमार्ग मार्गों पर 60.26 एमबीपीएस की उच्चतम औसत डाउनलोड गति दर्ज की, जिसके बाद एयरटेल क्रमशः 50.93 एमबीपीएस और 41.60 एमबीपीएस के साथ दूसरे स्थान पर रहा। बीएसएनएल ने कई परीक्षण खंडों में सबसे अधिक कवरेज अंतराल और कॉल ड्रॉप दर्ज किए, जबकि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने शहरी क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से कम कॉल ड्रॉप की सूचना दी। टीआरएआई ने कहा कि आवश्यक सुधारात्मक उपायों के लिए इन निष्कर्षों को सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ साझा किया गया है, जबकि विस्तृत रिपोर्ट इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। गैंगटोक के संदर्भ में, यह रिपोर्ट व्यवसायों, पर्यटन ऑपरेटरों और उन उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है जो निर्बाध डिजिटल कनेक्टिविटी पर अत्यधिक निर्भर हैं। बेहतर मोबाइल नेटवर्क गुणवत्ता गैंगटोक में डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन वाणिज्य, पर्यटन सेवाओं और उद्यम संचालन को सुदृढ़ कर सकती है, जबकि इस मूल्यांकन से दूरसंचार कंपनियों को इस क्षेत्र की बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में नेटवर्क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।